ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 8.4
IJAR 2023; 9(1): 243-246
www.allresearchjournal.com
Received: 06-11-2022
Accepted: 09-12-2022

डॉ. सीमा मलिक
असिस्टेंट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, गोकुलदास हिंदू गर्ल्स कॉलेज, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत

Corresponding Author:
डॉ. सीमा मलिक
असिस्टेंट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, गोकुलदास हिंदू गर्ल्स कॉलेज, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत

भारत में बेरोजगारी एक ज्वलंत समस्या कारण एवं समाधान

डॉ. सीमा मलिक

सारांश
तेजी से बढ़ती जनसंख्या वाले देश भारत के लिए बेरोजगारी एक मूलभूत एवं गंभीर समस्या है। दीर्घकालीन नियोजन के बावजूद यह देश में व्यापक रूप से फैली हुई है और तेजी के साथ यह बढ़ती ही जा रही है। ग्रामीण हो या शहरी, शिक्षित हो या अशिक्षित आज सभी बेरोजगारी से ग्रस्त हैं। भारत में बेरोजगारी ने देश के समक्ष विकट समस्या उत्पन्न कर दी है जिसके कारण गरीबों की संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है। बेरोजगारी एक ऐसी बुराई है जिसके दुष्परिणाम देश एवं समाज दोनों के लिए घातक होते हैं। कई बार बेरोजगार व्यक्ति अभावग्रस्त होने के कारण अपनी व परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए विवश होकर कोई भी अनैतिक कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं जिसका खामियाजा पकड़े जाने पर उन्हें व उनके परिवार को सारी उम्र झेलना पड़ता है। लोगों को एक सुखद जीवन देने एवं देश व समाज की तरक्की के लिए बेरोजगारी जैसे ज्वलंत समस्या का समाधान आवश्यक है।

कूटशब्द: बेरोजगारी, रोजगारपरक कार्यक्रम,अनैतिकता, गरीबी, जनसंख्या वृद्धि, अशिक्षा एवं अज्ञानता।

प्रस्तावना
जब हमारा देश भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय देश में ना तो विशाल जनसंख्या थी और ना उसके दुष्परिणाम के रूप में तीव्र गति के साथ बढ़ती हुई बेरोजगारी लेकिन समय बीतने के साथ-साथ स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हुआ जिससे भारत में जनसंख्या विस्फोट के दौर की शुरुआत हो गई। शिक्षा के प्रसार एवं महिलाओं के रोजगार पाने की लालसा के कारण श्रम की पूर्ति में बेतहाशा वृद्धि हुई है जिससे हर व्यक्ति के लिए रोजगार मिल पाना असंभव हो गया है। मई 2021 में जहां शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी की दर 13.90% थी वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की दर 10.60% रही।

बेरोजगारी का अर्थ एवं स्वरूप
जब कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से कार्य करने में समर्थ हो और वह प्रचलित मजदूरी दर पर काम करना चाहे ताकि वह अपनी आजीविका चला सके परंतु फिर भी उसे कोई काम ना मिले तो उस व्यक्ति को बेरोजगार कहा जाएगा। वास्तव में बेरोजगारी वह दशा है जिससे कार्य करने के इच्छुक व्यक्ति को काम चाहने की इच्छा के बावजूद प्रचलित मजदूरी दर पर काम नहीं मिलता है।

आमतौर पर किसी भी देश में सभी श्रमिक काम पर नहीं लगे होते। कुछ लगे होते हैं, कुछ खाली रहते हैं। किसी को वर्ष के कुछ महीने काम मिलता है। कहीं पर व्यक्ति को अपनी योग्यता के हिसाब से काम नहीं मिलता। भारत के संदर्भ में यह बातें विशेष रूप से लागू होती हैं। भारत में विशाल आबादी की वजह से बेरोजगारी के विभिन्न स्वरूप पाए जाते हैं।

जब किसी भी देश में पूंजी के साधन सीमित मात्रा में होते हैं और काम चाहने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जाती है तो पूंजी साधनों की कमी की वजह से कुछ व्यक्ति बिना काम के ही रह जाते हैं। भारत में भी पूंजी साधनों की कमी की वजह से संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। अधिक पढ़ा-लिखा होने पर भी जब योग्यता के हिसाब से काम नहीं मिलता तब व्यक्ति जीविकोपार्जन के लिए मजबूर होकर अपनी क्षमता से कम वाला कार्य करने के लिए विवश हो जाता है। जो अल्प रोजगार के रूप में हमारे सामने आता है। भारत में व्यक्ति को जब चाहने के बावजूद भी कोई काम नहीं मिलता तो यह खुली बेरोजगारी के प्रकार के रूप में हमारे सामने आता है। भारत में कृषि में मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। जब कृषक वर्ष के कुछ महीने काम करते हैं और कुछ महीने खाली रहते हैं। जब खेतों में जुताई एवं बुवाई का मौसम होता है तो कृषि में काम होता है लेकिन बीच के समय में इतना काम नहीं होता। कृषि में मौसमी बेरोजगारी के साथ-साथ छिपी बेरोजगारी भी पाई जाती है। खेती में जहां चार लोगों के काम की आवश्यकता होती है वहां 8-9 लोग उसी काम में लगे होते हैं जो दिखते तो काम करते हैं लेकिन वास्तव में वे लोग बेरोजगार होते हैं। यदि उन्हे वहां से हटाकर किसी और काम में लगा दिया जाए तो उससे उत्पादन क्षमता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। भारत में शिक्षित बेरोजगारी भी पाई जाती है जिसमें पढ़ा-लिखा व्यक्ति नौकरी ना मिलने के कारण खाली रहता है अल्प रोजगार की स्थिति में रहता है। भारत में इस प्रकार की बेरोजगारों की संख्या काफी है।

भारत में बढ़ती बेरोजगारी के कारण

1. विश्व में जनसंख्या के मामले में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। जनसंख्या 1.64% की दर से बढ़ रही है जबकि रोजगार सुविधाएं उस दर से नहीं बन रही हैं।
2. मशीनीकरण- हाथ से जो काम एक व्यक्ति 10-12 दिनों में करता है वह कार्य मशीन 1 घंटे में कर देती है।
3. दोषपूर्ण शिक्षा व्यवस्था- हमारे देश में शिक्षा का ढांचा सिद्धांत प्रधान शिक्षा पर आधारित है जबकि इसको व्यवसाय प्रधान होना चाहिए।
4. धीमी गति से पूंजी निर्माण- देश में पूंजी निर्माण की गति बहुत ही धीमी रही है जिसके कारण उद्योगों व्यवसायों व सेवाओं का विस्तार भी धीमी गति से हुआ है।
5. उदारीकरण- वर्ष 1991 में आर्थिक उदारीकरण को अपनाने के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में कई बदलाव आए जिससे देश का विदेशी मुद्रा भंडार तो बढ़ा लेकिन उद्योग धंधों में लगे श्रमिकों के लिए कई प्रकार की समस्याएं जन्म लेने लगीं।
6. महिलाओं द्वारा नौकरी- आजादी से पूर्व देश में बहुत कम महिलाएं नौकरी करती थीं लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या एवं प्रतिशत पहले से कहीं अधिक है। इससे पुरुषों में बेरोजगारी बढ़ी है।
7. दोषपूर्ण दृष्टिकोण- भारत में बेरोजगारी का एक महत्वपूर्ण कारण शिक्षित व्यक्तियों द्वारा नौकरी चाहने की इच्छा है। वे स्वयं कोई उत्पादन कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहते हैं। इस सोच ने भी आग में घी डालने का काम किया है।
8. बेरोजगारी के कुछ अन्य कारण- बेरोजगारी का एक बड़ा कारण दोषपूर्ण आर्थिक नियोजन है। रोजगार चाहने वालों के लिए पर्याप्त जानकारी ना मिलना भी बेरोजगारी का एक बड़ा कारण है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय से विद्यमान धार्मिक रीति रिवाज, कुरीतियां, परंपराएं व अंधविश्वास भी इनकी गतिशीलता में बाधा डालते हैं। एक तिहाई जनसंख्या क्योंकि गांव में रहती है ऐसे में उनकी गतिविधियां देश को प्रभावित करती हैं।

ज्वलंत समस्या बेरोजगारी के दुष्परिणाम

किसी भी राष्ट्र के लिए बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है जिसके भयंकर दुष्परिणाम किसी भी बेरोजगारी से ग्रस्त राष्ट्र को झेलने पड़ सकते हैं। बेरोजगारी के कारण मानव शक्ति का उचित उपयोग नहीं हो पाता और यह शक्ति व्यर्थ ही चली जाती है। यदि इसको ठीक प्रकार से काम में लिया जाए तो यह राष्ट्र के लिए समृद्धि एवं संपन्नता का साधन बन सकती है।

जिस देश में बेरोजगारी होती है उस देश में नई-नई सामाजिक समस्याएं जैसे चोरी,डकैती,बेईमानी, अनैतिकता,शराब खोरी, जुए बाजी ,सुपारी लेकर हत्या करना,अपहरण करके फिरौती वसूलने जैसी ना जाने कितनी समस्याएं पैदा हो जाती हैं जिससे सामाजिक सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था को खतरा पैदा हो जाता है।

राजनीतिक स्तर पर कभी भी अस्थिरता पैदा हो जाती है क्योंकि व्यक्ति हर समय राजनीतिक उखाड़-पछाड़ में लगे रहते हैं। बेरोजगारी के कारण आर्थिक संपन्नता में भी कमी आती है। व्यक्ति का जीवन स्तर गिरने लगता है। ऋणग्रस्तता बढ़ने लगती है। बेरोजगारी के परिणाम स्वरूप औद्योगिक संघर्षों में वृद्धि होने लगती है। मशीनीकरण के कारण जब मालिक मजदूरों की छटनी करते हैं तो उनमें आक्रोश फैल जाता है। मालिकों द्वारा बेरोजगारी का लाभ उठाकर उन्हें कम मजदूरी दी जाती है जिसका दुष्प्रभाव उनके खानपान एवं स्वास्थ्य पर पड़ता है। इस प्रकार बेरोजगारी से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक वातावरण दूषित हो जाता है। ऐसे में कोई भी राष्ट्र कैसे तरक्की कर सकता है एवं कैसे खुशहाल बन सकता है।

कोरोनाकाल के दौरान बेरोजगारी दर

सर्वे के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में अप्रैल से जून की पहली तिमाही में सबसे ज्यादा 20.8% की बेरोजगारी थी। यह वह दौर था जब देश में कोरोना के कहर के बीच सख्त लॉकडाउन लगा हुआ था। आंकड़ों के अनुसार मार्च 2021 में खत्म तिमाही में 15 साल से ऊपर के लोगों में श्रमबल भागीदारी दर पूरे देश में 47.3% थी जबकि इसकी पिछली यानी दिसंबर 2020 में खत्म तिमाही में यह 47.2% थी। एक साल पहले दिसंबर 2019 की तिमाही में यह 47.8% थी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सभी राज्यों में हरियाणा बेरोजगारी के मामले में सबसे आगे है। यहां 37.3% बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। दूसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर है जहां यह दर 32.8% है। तीसरे स्थान पर राजस्थान है जहां बेरोजगारी दर 31.4% है।

बेरोजगारी दर

(4 मार्च 2020)
भारत-8.0%
शहरी-8.9%
ग्रामीण-7.6%

राज्यवार बेरोजगारी के आंकड़े

हरियाणा-37.3%
जम्मू कश्मीर-32.8%
राजस्थान-31.4%
झारखंड-17.3%
त्रिपुरा-16.3%
छत्तीसगढ़-0.4%
मेघालय- 2%
महाराष्ट्र-2.2%
गुजरात और उडीसा-2.6%

भारत में बेरोजगारी को दूर करने के उपाय एवं सरकार द्वारा किए गए प्रयास-

1. जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण-भारत में सरकार द्वारा कानून बनाकर जनसंख्या पर नियंत्रण लगाया जाना चाहिए। इससे श्रमिकों की पूर्ति दर में कमी आएगी जिससे बेरोजगारी कम होगी।
2. कुटीर एवं लघु उद्योगों का विकास- कुटीर एवं लघु उद्योगों का विस्तार किया जाना चाहिए जिससे कि कम पूंजी विनियोग पर अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिल सके। इसके लिए श्रम प्रधान लघु उद्योगों का विकास किया जाना चाहिए।
3. कृषि पर आधारित उद्योग धंधों का विकास- गांव में कृषि सहायक उद्योग धंधों का विकास किया जाना चाहिए जिससे कि कृषक खाली समय में भी कुछ कार्य कर सकें। इसके लिए मुर्गी पालन, पशु पालन, बागवानी, दुग्ध व्यवसाय, मछली पालन, मधुमक्खी पालन आदि जैसे उद्योग धंधों का विकास किया जा सकता है।
4. विनियोग दर में वृद्धि- रोजगार सुविधाओं को बढ़ाने के लिए घरेलू बचतों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए जिसमें पूंजी निर्माण ऊंची दर से किया जा सके। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में बड़े पैमाने पर पूंजी का विनियोग कर बेरोजगारी को काफी हद तक कम किया जा सकता है।
5. सामान्य रोजगार- सरकार ने उद्योगों में भारी विनियोग करके रोजगार सुविधाएं बढ़ाने का उपाय किया है। प्रशिक्षणार्थी का विस्तार हुआ है जिससे कि अधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा सके। साख व अन्य आवश्यक इनपुट उपलब्ध किए गए हैं साथ ही गांवों व शहरों में अनेक रोजगार कार्यक्रम चालू किए गए हैं जिनमें प्रमुख है- स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, जयप्रकाश नारायण रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना।
6. विशिष्ट रोजगार- शिक्षित वर्ग में बेरोजगारी कम करने के लिए कुछ विशिष्ट रोजगार कार्यक्रम भी अपनाए गए हैं जैसे- स्कूलों की संख्या बढ़ाकर नवीन अध्यापकों को नियुक्त किया गया है।
7. बेरोजगारी भत्ता- विभिन्न राज्य सरकारें अपने-अपने राज्य में पंजीकृत बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दे रही हैं।
8. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना- भारत में 2 फरवरी 2006 को इस योजना

को लागू किया गया। इस योजना के माध्यम से भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को वर्ष में 100 दिन काम की कानूनी गारंटी देने की व्यवस्था की गई है।

निष्कर्ष

इस प्रकार विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर वाले विकासशील देश भारत में यद्यपि सरकार द्वारा बेरोजगारी को कम करने के लिए अनेकों कार्यक्रमों एवं योजनाओं को लगातार अमल में लाया जा रहा है लेकिन फिर भी यह समस्या अभी भी अपने ज्वलंत रूप में विद्यमान है जिसके लिए अभी और भी भागीरथ प्रयास करने की नितान्त आवश्यकता है ताकि इस गंभीर समस्या पर काबू पाया जा सके।

संदर्भ

1. भारतीय आर्थिक समस्याएं-डॉक्टर जे सी पंत एवं डॉक्टर जे बी सिंह
2. भारतीय अर्थव्यवस्था- डॉक्टर बी सी सिन्हा
3. भारतीय अर्थव्यवस्था- वी के पुरी एवं एस के मिश्र
4. भारतीय अर्थव्यवस्था- संजीव वर्मा
5. दैनिक समाचार पत्र- हिंदुस्तान
6. दैनिक समाचार पत्र- दैनिक जागरण
7. इंटरनेट